

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्गा/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 4 अक्टूबर 2024—अश्विन 12, शक 1946

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 20 अगस्त 2024

क्रमांक ई 1-03/2024/एक-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अभिजीत सिंह, भा.प्र.से. (2012), संयुक्त सचिव, गृह एवं जेल विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

2. श्री प्रभात मलिक, भा.प्र.से. (2015), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), रायपुर तथा अतिरिक्त प्रभार संयुक्त सचिव, सुशासन एवं अभिसरण विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ संयुक्त सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश कुमार बंसल, सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 10 सितम्बर 2024

क्रमांक ई 1-03/2024/एक-2.—राज्य शासन एतद्वारा श्रीमती ऋचा शर्मा, भा.प्र.से. (1994) अपर मुख्य सचिव, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अपर मुख्य सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

2. श्री रजत कुमार, भा.प्र.से. (2005) को केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस लौटने पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग (रेल परियोजनायें) विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

श्री रजत कुमार, भा.प्र.से. द्वारा सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग (रेल परियोजनायें) विभाग का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से श्री पी. दयानंद, भा.प्र.से. (2006), सचिव, माननीय मुख्यमंत्री तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव, ऊर्जा विभाग, सचिव, खनिज साधन विभाग, सचिव, जनसंपर्क विभाग, अध्यक्ष, छ.ग. स्टेट पावर कंपनी, सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग (रेल परियोजनायें) विभाग, सचिव, विमानन विभाग केवल सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग (रेल परियोजनायें) विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

3. श्री अंकित आनंद, भा.प्र.से. (2006), सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग तथा अति. प्रभार सचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, सचिव, बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए सचिव, बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग एवं अध्यक्ष, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

श्री अंकित आनंद, भा.प्र.से. द्वारा सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग तथा अध्यक्ष, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सुश्री आर. शंगीता, भा.प्र.से. (2005), सचिव, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग, अध्यक्ष, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, आबकारी आयुक्त केवल सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग तथा अध्यक्ष, छ.ग. पर्यावरण मंडल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी। शेष प्रभार यथावत रहेगा।

4. श्री बसवराजू एस., भा.प्र.से. (2007), सचिव, माननीय मुख्यमंत्री तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को केवल सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए सचिव, विमानन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

श्री बसवराजू एस., भा.प्र.से. द्वारा सचिव, विमानन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से श्री पी. दयानंद, भा.प्र.से. (2006), सचिव, माननीय मुख्यमंत्री तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव, ऊर्जा विभाग, सचिव, खनिज साधन विभाग, सचिव, जनसंपर्क विभाग, अध्यक्ष, छ.ग. स्टेट पावर कंपनी, सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग (रेल परियोजनायें) विभाग, सचिव, विमानन विभाग केवल सचिव, विमानन विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

5. श्री भीम सिंह, भा.प्र.से. (2008), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. राज्य ग्रामीण विकास अभिकरण को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. राज्य ग्रामीण विकास अभिकरण का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

6. श्री राजेश सिंह राणा, भा.प्र.से. (2008), सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, क्रेडा एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. राज्य कौशल विकास अधिकरण को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, क्रेडा के पद पर पदस्थ करते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. राज्य कौशल विकास अधिकरण का अति. प्रभार सौंपता है।

श्री राजेश सिंह राणा, भा.प्र.से. द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, क्रेडा का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, क्रेडा के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

7. श्री भूरे सर्वेश्वर नरेन्द्र, भा.प्र.से. (2011), सचिव, छ.ग. राज्य निर्वाचन आयोग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ मिशन संचालक, जल जीवन मिशन का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

श्री भूरे सर्वेश्वर नरेन्द्र, भा.प्र.से. द्वारा मिशन संचालक, जल जीवन मिशन का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से श्री सुनील कुमार जैन भा.प्र.से. (2009), संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म तथा अतिरिक्त प्रभार विशेष सचिव, खनिज साधन विभाग, विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग, मिशन संचालक, जल जीवन मिशन, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य खनिज विकास निगम केवल मिशन संचालक, जल जीवन मिशन के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे। शेष प्रभार यथावत रहेगा।

8. श्री जितेन्द्र कुमार शुक्ला, भा.प्र.से. (2011), प्रबंध संचालक, छ.ग. पर्यटन मंडल, रायपुर तथा अति. प्रभार संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के पद पर पदस्थ करता है।

9. श्री प्रभात मलिक, भा.प्र.से. (2015), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), रायपुर तथा अतिरिक्त प्रभार संयुक्त सचिव, सुशासन एवं अभिसरण विभाग, संयुक्त सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ संचालक, उद्योग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

श्री प्रभात मलिक, भा.प्र.से. द्वारा संचालक, उद्योग का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से श्री अरूण प्रसाद पी., भा.व.से. (2006), सदस्य-सचिव, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल तथा अतिरिक्त प्रभार संचालक, उद्योग एवं प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य औद्योगिक विकास निगम केवल संचालक, उद्योग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

10. श्री विवेक आचार्य, भा.व.से. (2006), संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ प्रबंध संचालक, छ.ग. पर्यटन मंडल का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

11. श्री विश्वेश कुमार, भा.व.से. (2007), प्रभारी मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) एवं क्षेत्र संचालक, उदंती-सीतानदी टायगर रिजर्व, गरियाबंद की सेवायें वन विभाग से प्रतिनियुक्ति पर लेते हुए आगामी आदेश पर्यन्त प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य औद्योगिक विकास निगम के पद पर पदस्थ करता है।

श्री विश्वेश कुमार भा.व.से. द्वारा प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य औद्योगिक विकास निगम का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से श्री अरूण प्रसाद पी., भा.व.से. (2006), सदस्य-सचिव, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल तथा अतिरिक्त प्रभार संचालक, उद्योग एवं प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य औद्योगिक विकास निगम केवल प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य औद्योगिक विकास निगम के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्वेष घृतलहरे, अवर सचिव.

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 14 अगस्त 2024

क्रमांक एफ 01-02/2024/10-भा.व.से.—विभाग के आदेश क्रमांक/1481/462/2021/10-भा.व.से., दिनांक 16-08-2021 द्वारा श्री जे.ए.सी.एस. राव, भा.व.से. (1987) को, दिनांक 30-06-2021 से सेवानिवृत्ति पश्चात् छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 के नियम 4(2) में उल्लेखित प्रावधान अंतर्गत उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्ष के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ आदिवासी, स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड, रायपुर के पद पर संविदा नियुक्ति प्रदान की गई है, जिसकी अवधि दिनांक 15-08-2024 को समाप्त होगी।

2. अतः राज्य शासन एतद्वारा श्री जे.ए.सी.एस. राव, भा.व.से. (1987) को उनकी सेवा निवृत्ति उपरांत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ आदिवासी, स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड, रायपुर के पद पर दी गई संविदा नियुक्ति की अवधि दिनांक 15-08-2024 को समाप्त होने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक/एफ 9-1/2012/1-3, दिनांक 13-05-2024 द्वारा छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 एवं उसमें समय-समय पर किये गये संशोधनों एवं जारी दिशा-निर्देश अनुसार उनकी संविदा नियुक्ति की अवधि में दिनांक 16-08-2024 से 01 वर्ष की वृद्धि करता है।

3. श्री राव की संविदा नियुक्ति की शर्तें सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक/एफ 9-1/2012/1-3, दिनांक 13-05-2024 द्वारा छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 एवं उसमें समय-समय पर किये गये संशोधनों एवं जारी दिशा-निर्देश तथा शर्तों के अनुसार रहेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. आर. चन्द्रवंशी, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 12 अगस्त 2024

प्रारूप-एक
(नियम-11 देखिये)

क्रमांक/11445/भू-अर्जन/2024.— भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	पोंड़ी उपरोड़ा	रामपुर	1.314 हे.	रामपुर जलाशय योजना अंतर्गत दांयी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 02-09-2024 को समय 12.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन, रामपुर में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(1)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	रामपुर जलाशय योजना अंतर्गत दांयी तट मुख्य नहर निर्माण के लिये अर्जित होने पर.
(2)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	19 परिवार
(3)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	19 परिवार
(4)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(5)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(6)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(7)	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
(8)	परियोजना की कुल लागत	—	रु. लाख
(9)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	रामपुर जलाशय योजना अंतर्गत नहर निर्माण होने से सिंचाई की रकबा प्रभावित होने से फसल की पैदावार में वृद्धि होगी.
(10)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये आवेदित संस्था के द्वारा संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है.
(11)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 12 अगस्त 2024

प्रारूप-एक
(नियम-11 देखिये)

क्रमांक/11449/भू-अर्जन/2024.— भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	पोंड़ी उपरोड़ा	तनाखार	20.887 हे.	रामपुर जलाशय योजना अंतर्गत शीर्ष निर्माण हेतु

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 04-09-2024 को समय 12.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन, तानाखार में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(1)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	रामपुर जलाशय योजना अंतर्गत शीर्ष निर्माण हेतु अर्जित होने पर.
(2)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	63 परिवार
(3)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	63 परिवार
(4)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(5)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(6)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(7)	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
(8)	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 8340.45 लाख
(9)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	रामपुर जलाशय योजना अंतर्गत शीर्ष निर्माण होने से सिंचाई की रकबा प्रभावित होने से फसल की पैदावार में वृद्धि होगी.
(10)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये आवेदित संस्था के द्वारा संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है.
(11)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 12 अगस्त 2024

प्रारूप-एक
(नियम-11 देखिये)

क्रमांक/11453/भू-अर्जन/2024.— भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	पोंड़ी उपरोड़ा	डगनिया	24.149 हे.	रामपुर जलाशय योजना अंतर्गत शीर्ष निर्माण हेतु

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 03-09-2024 को समय 12.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन, गुड़रुमुड़ा में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(1)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	रामपुर जलाशय योजना अंतर्गत शीर्ष निर्माण हेतु अर्जित होने पर.
(2)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	66 परिवार
(3)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	66 परिवार
(4)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(5)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(6)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(7)	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
(8)	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 8340.45 लाख
(9)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	रामपुर जलाशय योजना अंतर्गत शीर्ष निर्माण होने से सिंचाई की रकबा प्रभावित होने से फसल की पैदावार में वृद्धि होगी.
(10)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये आवेदित संस्था के द्वारा संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है.
(11)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 22 अगस्त 2024

प्रारूप-एक
(नियम-11 देखिये)

क्रमांक/11942/क/भू-अर्जन/202103050500001/अ-82/2020-21.— भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	करतला	घिनारा	2.090 हे.	घिनारा व्यपवर्तन योजना का शीर्ष एवं नहर निर्माण

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 03-10-2024 को समय 12.00 बजे से स्थान ग्राम घिनारा नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	घिनारा व्यपवर्तन योजना का शीर्ष एवं नहर निर्माण
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	14
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
7.	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	534.89 लाख
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	सिंचाई की सुविधा
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 22 अगस्त 2024

प्रारूप-एक
(नियम-11 देखिये)

क्रमांक/11946/क/भू-अर्जन/202103050500002/अ-82/2020-21.— भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	करतला	सेन्द्रीपाली	4.374 हे.	घिनारा व्यपवर्तन योजना का दायीं तट नहर एवं माईनर नहर निर्माण.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 28-09-2024 को समय 12.00 बजे से स्थान ग्राम सेन्द्रीपाली नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	घिनारा व्यपवर्तन योजना का दांयी तट नहर एवं माइनर नहर निर्माण.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	26
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
7.	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	534.89 लाख
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	सिंचाई की सुविधा
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजीत वसंत, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग**

बिलासपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2024

प्रारूप-एक
(नियम-11 देखिये)

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/20/अ-82/2023-24.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
बिलासपुर	कोटा	मनपहरी	2.805 हेक्टेयर	घोंघा जलाशय योजना के मनपहरी एवं खरगा माईनर नहर कार्य.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 30-9-2024 को (समय) 11.00 बजे (स्थान ग्राम पंचायत भवन ग्राम मनपहरी पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	घोंघा जलाशय योजना के मनपहरी एवं खरगा माईनर नहर कार्य.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	—
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	—
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(सात)	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	घोंघा जलाशय योजना के मनपहरी एवं खरगा माईनर नहर कार्य.
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	963.897
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	खरीफ सिंचाई सुविधा का विस्तार
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	भूमि अर्जन पुनर्वासन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 द्वारा दर्शायी गई तथा समय-समय पर छ.ग. शासन द्वारा बताया गया उपाय का अनुपालन किया जावेगा तथा सम्भावित व्यय रु. पांच लाख या वास्तविक व्यय जो भी अधिक हो.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनीश कुमार शरण, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 20 अगस्त 2024

प्र. क्रमांक 202301042100040/अ-82/2022-23. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की केलो परियोजना के अंतर्गत पुटकापुरी माइनर नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता होने पर भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के अनुसार अधिग्रहण हेतु छ.ग. के राजपत्र में दिनांक 05-05-2023 को प्रकाशित किया गया था, किन्तु उक्त प्रकरण में नियमानुसार धारा-19 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की जाने वाली अंतिम अधिसूचना के पूर्व उपधारा (2) के द्वितीय परन्तुक के तहत अपेक्षक निकाय से अंशतः एवं भागतः राशि प्राप्त नहीं होने से नियत समयावधि में धारा-19 अधिसूचना घोषणा का प्रकाशन नहीं कराया जा सका. आवेदक ईकाई द्वारा भागतः 10 प्रतिशत राशि जमा किये जाने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा-19 की उपधारा 7 में वर्णित प्रावधानों एवं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 12 मास (01 वर्ष) की समयावधि वृद्धि की जाती है एवं जन साधारण हेतु सूचना/प्रकाशित की जाती है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	गोतमा प.ह.नं. 34	0.020	कार्यपालन अभियंता, केलो परि- योजना निर्माण संभाग लाखा, अ.मु. खरसिया, जिला-रायगढ़ (छ.ग.).	केलो परियोजना के वृहद सिंचाई योजनांतर्गत टिनमिनी माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

रायगढ़, दिनांक 20 अगस्त 2024

प्र. क्रमांक 202302042100051/अ-82/2022-23. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की केलो परियोजना के अंतर्गत कुसुमुरा माइनर व औराभाठा माइनर नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता होने पर भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के अनुसार अधिग्रहण हेतु छ.ग. के राजपत्र में दिनांक 05-05-2023 को प्रकाशित किया गया था, किन्तु उक्त प्रकरण में नियमानुसार धारा-19 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की जाने वाली अंतिम अधिसूचना के पूर्व उपधारा (2) के द्वितीय परन्तुक के तहत अपेक्षक निकाय से अंशतः एवं भागतः राशि प्राप्त नहीं होने से नियत समयावधि में धारा-19 अधिसूचना घोषणा का प्रकाशन नहीं कराया जा सका. आवेदक ईकाई द्वारा भागतः 10 प्रतिशत राशि जमा किये जाने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा-19 की उपधारा 7 में वर्णित प्रावधानों एवं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 12 मास (01 वर्ष) की समयावधि वृद्धि की जाती है एवं जन साधारण हेतु सूचना/प्रकाशित की जाती है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	बालमगोड़ा प.ह.नं. 19	0.138	कार्यपालन अभियंता, केलो परि- योजना निर्माण संभाग लाखा, अ.मु. खरसिया, जिला-रायगढ़ (छ.ग.).	केलो परियोजना के अंतर्गत कुसुमुरा माइनर व औराभाठा नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

रायगढ़, दिनांक 20 अगस्त 2024

प्र. क्रमांक 202302042100052/अ-82/2022-23.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की केलो परियोजना के अंतर्गत धनगांव माइनर-01 एवं सब-माइनर नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता होने पर भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के अनुसार अधिग्रहण हेतु छ.ग. के राजपत्र में दिनांक 05-05-2023 को प्रकाशित किया गया था, किन्तु उक्त प्रकरण में नियमानुसार धारा-19 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की जाने वाली अंतिम अधिसूचना के पूर्व उपधारा (2) के द्वितीय परन्तुक के तहत अपेक्षक निकाय से अंशतः एवं भागतः राशि प्राप्त नहीं होने से नियत समयावधि में धारा-19 अधिसूचना घोषणा का प्रकाशन नहीं कराया जा सका. आवेदक ईकाई द्वारा भागतः 10 प्रतिशत राशि जमा किये जाने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा-19 की उपधारा 7 में वर्णित प्रावधानों एवं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 12 मास (01 वर्ष) की समयावधि वृद्धि की जाती है एवं जन साधारण हेतु सूचना/प्रकाशित की जाती है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	नावापारा प.ह.नं. 17	0.275	कार्यपालन अभियंता, केलो परि- योजना निर्माण संभाग लाखा, अ.मु. खरसिया, जिला-रायगढ़ (छ.ग.).	केलो परियोजना के अंतर्गत धनगांव माइनर 01 एवं सब-माइनर नहर निर्माण हेतु भू- अर्जन.

रायगढ़, दिनांक 20 अगस्त 2024

प्र. क्रमांक 202302042100053/अ-82/2022-23.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की केलो परियोजना के अंतर्गत पुटकापुरी माईनर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता होने पर भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार अधिग्रहण हेतु अधिनियम की धारा-11 का छ.ग. के राजपत्र में दिनांक 05-05-2023 को प्रकाशित किया गया था, किन्तु उक्त प्रकरण में नियमानुसार धारा-19 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की जाने वाली अंतिम अधिसूचना के पूर्व उपधारा (2) के द्वितीय परन्तुक के तहत अपेक्षक निकाय से अंशतः एवं भागतः राशि प्राप्त नहीं होने से नियत समयावधि में धारा-19 अधिसूचना घोषणा का प्रकाशन नहीं कराया जा सका. आवेदक ईकाई द्वारा भागतः 10 प्रतिशत राशि जमा किये जाने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा-19 की उपधारा 7 में वर्णित प्रावधानों एवं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 12 मास (01 वर्ष) की समयावधि वृद्धि की जाती है एवं जन साधारण हेतु सूचना/प्रकाशित की जाती है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	पुटकापुरी प.ह.नं. 16	0.093	कार्यपालन अभियंता, केलो परि- योजना निर्माण संभाग लाखा, अ.मु. खरसिया, जिला-रायगढ़ (छ.ग.).	केलो परियोजना योजनांतर्गत पुटकापुरी माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

रायगढ़, दिनांक 20 अगस्त 2024

प्र. क्रमांक 202302042100086/अ-82/2022-23.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की केलो परियोजना के अंतर्गत सिंहा माईनर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता होने पर भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार अधिग्रहण हेतु अधिनियम की धारा-11 का, छ.ग. के राजपत्र में दिनांक 05-05-2023 को प्रकाशित किया गया था, किन्तु उक्त प्रकरण में नियमानुसार धारा-19 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की जाने वाली अंतिम अधिसूचना के पूर्व उपधारा (2) के द्वितीय परन्तुक के तहत अपेक्षक निकाय से अंशतः एवं भागतः राशि प्राप्त नहीं होने से नियत समयावधि में धारा-19 अधिसूचना घोषणा का प्रकाशन नहीं कराया जा सका. आवेदक ईकाई द्वारा भागतः 10 प्रतिशत राशि जमा किये जाने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा-19 की उपधारा 7 में वर्णित प्रावधानों एवं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 12 मास (01 वर्ष) की समयावधि वृद्धि की जाती है एवं जन साधारण हेतु सूचना/प्रकाशित की जाती है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	सिंहा प.ह.नं. 35	1.236	कार्यपालन अभियंता, केलो परि- योजना निर्माण संभाग लाखा, अ.मु. खरसिया, जिला-रायगढ़ (छ.ग.).	केलो परियोजना वृहद सिंचाई योजनांतर्गत जिलाडी माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कार्तिकेया गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 22 अगस्त 2024

क्रमांक/11952/भू-अर्जन/202010050400007/अ-82/2024.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	करतला	बोकरदा प.ह.नं. 40	1.802	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कोरबा जिला कोरबा (छ.ग.)	बोकरदा जलाशय योजना के माईनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजीत वसंत, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग		(1)	(2)
रायगढ़, दिनांक 17 सितम्बर 2024		676/1	0.028
		676/4	0.012
		676/8	0.069
		678/1	0.235
		678/2	0.235
भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202212042100046/अ-82/2022-		686	0.073
23.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे		687/1	0.619
दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2)		687/2	0.081
में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि		685/1	0.073
अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता		519	0.283
का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम,		626/2	0.018
2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित		627 से.	0.041
किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता		636/4	0.129
है :—		628/1	0.041
		628/2	0.041
अनुसूची		646/3	0.085
		629	0.045
(1) भूमि का वर्णन-		513/2	0.141
(क) जिला-रायगढ़		619/1	0.200
(ख) तहसील-पुसौर		619/2	0.243
(ग) नगर/ग्राम-कोतमरा		616/2	0.101
(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.643 हेक्टेयर		643	0.121
		644	0.231
खसरा नम्बर		616/1	0.027
रकबा		616/3	0.027
(हेक्टेयर में)		616/4	0.027
(1)	(2)	615	0.050
		631	0.038
501/5क	0.150	636/2	0.125
501/2	0.445	636/3, 636/6	0.004
501/5ख	0.154	636/12, 636/13	0.040
504/2	0.162	636/1	0.154
505/3	0.143	652/1	0.182
505/4	0.144	646/1	0.085
521/3	0.142	646/2	0.049
624/1	0.190	648/1	0.075
624/2	0.063	637	0.081
624/3	0.063	648/2	0.076
624/4	0.064	648/3	0.076
665/1	0.040	665/5	0.057
665/3	0.093	665/18	0.040
665/7	0.073	665/17	0.032
665/8	0.032	679	0.101
670/2	0.069	540	0.073
672/1	0.223	512/1	0.041
672/2	0.174	528/4	0.041
674/1	0.178		

(1)	(2)	(1)	(2)
512/2	0.041	412/9/1	0.049
512/3	0.040	344/4/1	0.089
512/4	0.040	178/11/1	0.008
512/5	0.040	412/9/2	0.049
685/6	0.113	344/4/2	0.089
636/8, 636/9	0.040	178/11/2	0.008
636/10, 636/11	0.041	412/9/3	0.049
636/14, 636/15	0.040	344/4/3	0.089
		178/11/3	0.008
योग	73	345	0.053
		339/1	0.036
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजन रेल लाईन निर्माण हेतु.		353/36	0.057
		412/1	0.150
		412/2	0.231
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.		411/1	0.081
		411/7	0.081
		395/6	0.028
		424/1	0.045
रायगढ़, दिनांक 27 सितम्बर 2024		348/2	0.202
		339/2, 339/3	0.149
भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202211042100080/अ-82/2022-		411/2	0.028
23.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—		411/3	0.032
		178/6	0.032
		348/5	0.121
		395/4/1, 395/5/2	0.120
		353/5	0.049
		395/4/2	0.118
		414/3/1	0.069
		394/1/1	0.115
		383/4	0.008
अनुसूची		401/1, 415/2	0.160
		416	0.032
(1) भूमि का वर्णन—		352/1	0.142
(क) जिला-रायगढ़		397/2	0.053
(ख) तहसील-रायगढ़		426/16	0.049
(ग) नगर/ग्राम-उच्चभिट्टी		383/2	0.012
(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.025 हेक्टेयर		457/8, 458/8	0.401
		457/14, 458/14	0.235
खसरा नम्बर	रकबा	388/1, 389/1	0.081
	(हेक्टेयर में)	386/3	0.073
(1)	(2)	342/1	0.219
		387/3/5	0.170
339/9	0.097	385/1 क	0.034
339/15	0.036	387/1	0.047
353/37	0.073	385/1घ	0.016
412/8	0.110	385/3	0.034
412/10	0.061	387/4	0.064

(1)	(2)	(1)	(2)
385/4	0.034	177/27	0.040
387/5	0.064	177/9	0.024
385/1ढ/1	0.057	177/14/1	0.040
385/1ड/2	0.061	177/24	0.016
347/3	0.071	177/12	0.012
343/2	0.202		
348/12	0.101	योग	105
343/1	0.203		8.025
348/1	0.101		
352/2	0.057	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजन रेल लाईन निर्माण हेतु.	
700/2	0.016		
349	0.040	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.	
347/5	0.071		
348/4	0.283		
347/1	0.053		
382/2	0.028		
339/10	0.036	रायगढ़, दिनांक 27 सितम्बर 2024	
347/4	0.111		
408/1	0.073	भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202212042100050/अ-82/2022-	
391/7	0.085	23.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-	
391/8	0.094		
408/2	0.020		
391/3क/3	0.122		
409/2/1, 409/3/1	0.169		
415/1, 417/च	0.081		
415/1, 417/छ	0.061		
415/1, 417/ख	0.097		
415/1, 417/ड.	0.032		
415/1, 417/घ	0.015		
409/2/2	0.133		
391/3क/4	0.097		
391/3क/2	0.235		
347/2	0.044		
410/2	0.040		
383/6	0.008		
383/1	0.008		
382/1	0.028		
201/2	0.020		
198/1	0.020		
196/4/2	0.080		
196/12	0.016		
196/11	0.040		
186/5	0.016		
186/3	0.040		
186/4	0.040		
186/700/1/2	0.008		
186/700/1/1	0.008		
178/8	0.032		

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-रायगढ़
(ग) नगर/ग्राम-गेजामुड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.042 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
440/4	0.057
440/5	0.021
439/4	0.016
438/1, 439/1	0.061
440/1	0.020
440/2	0.038
438/4, 439/3	0.101

(1)	(2)	(1)	(2)
438/8	0.065	9	0.101
407	0.271	10	0.162
418/2	0.065	11	0.162
418/1	0.016	12	0.045
408/2 409, 410/2	0.012	150	0.101
412/2	0.041	152	0.101
437/2	0.099	151/1, 151/2	0.101
437/1	0.098	415/3, 416/3, 417/1/3	0.157
377/2	0.061	413/3/4, 414/2/4	0.040
412/1, 413/1	0.128	378/1	0.012
382स	0.101	415/1, 416/1, 417/1/1	0.016
381/1	0.135	413/4, 414/2	0.158
381/2	0.068	411/2	0.024
180/1, 180/2	0.182	417/2	0.028
168/2	0.027	378/2	0.028
172/1	0.141	374	0.032
381/3	0.060	149/3	0.081
172/3	0.146	149/2	0.275
180/3	0.070	177	0.008
168/4	0.004	4	0.040
168/7	0.007	408/1	0.008
168/1	0.073	406/2	0.004
168/6	0.080	406/1क	0.004
180/4	0.222	406/1ख	0.004
168/3	0.064	179/1	0.040
168/5	0.008		
375/2	0.020		
375/3	0.024	योग	67 5.042
169/1	0.190		
169/2	0.101	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजन रेल लाईन निर्माण हेतु.	
169/3	0.065		
170	0.061	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.	
156/3	0.020		
173	0.142		
7, 8	0.129	छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कार्तिकेया गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.	

विभाग प्रमुखों के आदेश

संचालनालय, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा
इन्द्रावती भवन, ब्लॉक-एक, द्वितीय तल, अटल नगर, नवा रायपुर

नवा रायपुर, दिनांक 20 अगस्त 2024

क्रमांक/सी.एस.ए./प्रशा./292/2020/122.—संचालनालय, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा, नवा रायपुर द्वारा माह-जुलाई 2024 (दिनांक 22-07-2024 से 26-07-2024 तक) में आयोजित “छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा, अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा भाग-एक एवं भाग-दो” में सम्मिलित निम्नानुसार कर्मचारियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा भाग-एक उत्तीर्ण

क्रमांक (1)	अनुक्रमांक (2)	कर्मचारी का नाम (3)	पदनाम (4)	वर्ग (5)	कार्यालय (6)
1.	241001	श्री वीरेन्द्र कुमार साहू	सहा. संपरीक्षक	अ.पि.व.	रायपुर-2
2.	241002	श्री हरीश कुमार नेताम (परि.),	सहायक ग्रेड-3	अ.ज.जा.	जगदलपुर
3.	241003	श्री संजय कुमार खुटे	सहायक ग्रेड-3	अ.जा.	रायगढ़

छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा भाग-दो उत्तीर्ण

क्रमांक (1)	अनुक्रमांक (2)	कर्मचारी का नाम (3)	पदनाम (4)	वर्ग (5)	कार्यालय (6)
1.	242001	श्री तरूण सिंह ठाकुर,	ज्येष्ठ संप. (परि.)	सामान्य	रायगढ़
2.	242002	श्री लोमेश सिंह राजपूत,	ज्येष्ठ संप. (परि.)	सामान्य	जगदलपुर
3.	242003	श्री गीता प्रसाद,	ज्येष्ठ संप. (परि.)	अ.पि.व.	राजनांदगांव
4.	242004	सुश्री शुभम शर्मा,	ज्येष्ठ संप. (परि.)	सामान्य	दुर्ग
5.	242005	श्री नवदीप डहरिया,	ज्येष्ठ संप. (परि.)	अ.जा.	रायगढ़
6.	242006	श्रीमती ज्योति रात्रे (बघेल),	ज्येष्ठ संप. (परि.)	अ.जा.	रायपुर-1
7.	242007	श्री अंकित कुमार भगत,	ज्येष्ठ संप. (परि.)	अ.ज.जा.	रायपुर-2
8.	242008	कु. प्रियंका मराबी,	ज्येष्ठ संप. (परि.)	अ.ज.जा.	रायपुर-2
9.	242009	श्रीमती लक्ष्मी देवी,	सहायक ग्रेड-1	अ.जा.	दुर्ग
10.	242011	श्री शशांक देवांगन,	सहा.संपरीक्षक	अ.पि.व.	राजनांदगांव
11.	242012	श्री दुबे लाल साहू,	सहा. संपरीक्षक	अ.पि.व.	संचालनालय
12.	242013	सुश्री नेहा रजक,	सहा. संपरीक्षक	अ.पि.व.	बिलासपुर
13.	242014	श्री सिद्धार्थ देवांगन,	सहा.संपरीक्षक	अ.पि.व.	बिलासपुर
14.	242015	श्री रोहित दास,	सहा.संपरीक्षक	अ.जा.	संचालनालय
15.	242016	श्री सरोज किशोर,	सहा.संपरीक्षक	अ.जा.	रायगढ़
16.	242017	श्रीमती अनिता,	सहा.संपरीक्षक	सामान्य	दुर्ग
17.	242018	श्री मनोज कुमार नेताम,	सहा.संपरीक्षक	अ.ज.जा.	जगदलपुर
18.	242019	श्री होमन कुमार ठाकुर,	सहा. संपरीक्षक	अ.ज.जा.	दुर्ग

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19.	242020	सुश्री कमलेश्वरी ठाकुर,	सहा. संपरीक्षक	अ.ज.जा.	रायपुर-1
20.	242021	श्री तुलेश्वर सिंह	सहा. संपरीक्षक	अ.ज.जा.	जगदलपुर
21.	202022	श्री कुंजबिहारी	सहा. संपरीक्षक	अ.ज.जा.	संचालनालय
22.	242023	श्री विक्रम सिंह,	सहा. संपरीक्षक	अ.ज.जा.	राजनांदगांव
23.	242025	श्री शरद डहरिया,	सहा. संपरीक्षक	अ.जा.	रायगढ़
24.	242026	श्री तुलसी प्रसाद श्रीवास,	सहा. संपरीक्षक	अ.पि.व.	रायगढ़
25.	242027	श्री अभिषेक कुमार सिन्हा,	डॉटा एन्ट्री ऑपरेटर	अ.पि.व.	संचालनालय
26.	242028	श्री अमित मिंज,	सहायक ग्रेड-3	अ.ज.जा.	संचालनालय

गिरीश कुमार पुरे,
परीक्षा नियंत्रक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

बिलासपुर, दिनांक 30 अगस्त 2024

क्रमांक 13800/चेकर/तीन-10-8/2000 (VIII).—छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958), की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर एतद्वारा अपनी अधिसूचना क्रमांक 13301/चेकर/तीन-10-8/2000 (VIII), बिलासपुर दिनांक 22-08-2024 में निम्नानुसार संशोधन करता है :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना की सारणी के सरल क्रमांक 23 के स्तंभ क्रमांक 4 में वर्णित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां संस्थापित की जाती हैं, अर्थात् :—

सारणी

क्रमांक	सिविल जिले का नाम	जिला न्यायाधीश के न्यायालय	
		बैठने का स्थान	न्यायालयों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
23.	उत्तर बस्तर (कांकेर)	1. कांकेर	2
		2. भानुप्रतापपुर	2

No. 13800/Checker/III-10-8/2000(VIII).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur hereby makes the following amendment in its Notification No. 13301/Checker/III-10-8-/2000(VIII), Bilaspur, dated 22-08-2024, namely :—

AMENDMENT

In the said notification of the table for the serial no. 23 and further existing entries relating thereto as shown in column No. (4) the following entries are substituted namely :—

TABLE

S. No.	Name of Civil District	Court of District Judges	
		Place of sitting	No. of Courts
(1)	(2)	(3)	(4)
23.	Uttar Bastar (Kanker)	1. Kanker	2
		2. Bhanupratappur	2

By Order of the High Court,
BALRAM PRASAD VERMA, Registrar General.
